

INVESTMENT AVENUES®

इन्वेस्टमेंट ऐवेन्यूस

भोपाल, शनिवार 12 से 18 जुलाई 2025

भोपाल, मध्यप्रदेश से प्रकाशित

वर्ष- 12

अंक-49

पृष्ठ- 8

मूल्य- रु. 5 /-

लुधियाना इंटरैक्टिव सेशन का शानदार आयोजन, मिले 15,606 करोड़ के निवेश प्रस्ताव, 20 हजार से अधिक रोजगार का होगा सृजन

बिजनेस डेस्क: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को 7 जुलाई 2025 को लुधियाना में मध्यप्रदेश की निवेश संभावनाओं पर आयोजित 'इंटरैक्टिव सेशन' का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रमुख उद्योगपति व निवेशकों की उपस्थिति में मुख्यमंत्री जी ने मध्यप्रदेश की विशेषताएं बताते हुए उन्हें निवेश के लिए आमंत्रित किया... इस सफल कॉन्क्लेव में 15600 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए... जिनके माध्यम से प्रदेश में 20 हजार से अधिक नए रोजगारों का सृजन होगा...

देश का आर्थिक तंत्र मजबूत हुआ : CM

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि देश का आर्थिक तंत्र मजबूत हुआ है। देश में औद्योगीकरण बढ़ा है, अब हम विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। लुधियाना भारत का मैनेस्टर है। यहां के उद्योगपतियों ने बड़ी मेहनत से अपनी पहचान बनाई है। लुधियाना में निर्मित ए-वन और हीरो साइकिल्स देश-दुनिया में मशहूर हैं। पंजाब के निवेशक देश की आर्थिक समृद्धि में योगदान देने वाले प्रमुख ध्वजवाहक हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज लुधियाना में हुये इंटरैक्टिव सेशन, वन-टू-वन चर्चा और संवाद सत्रों में यहां के उद्योगपतियों से 15 हजार 606 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं, जिससे 20 हजार से अधिक रोजगार का सृजन होगा। हमने लुधियाना और पंजाब के उद्योगपतियों को मध्यप्रदेश में उद्योग लगाने के लिये आमंत्रित किया। साथ ही उन्हें मध्यप्रदेश में उपलब्ध संसाधनों के साथ राज्य की औद्योगिक नीतियों से भी अवगत कराया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार को पंजाब की उद्योग नगरी लुधियाना में मध्यप्रदेश में निहित निवेश की संभावनाओं के संबंध में निवेशकों को संबोधित कर रहे थे।

उद्योग-धंधे लगाने के लिए भूमि, बिजली, पानी, कुशल कार्यशक्ति सब उपलब्ध

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश देश का एकमात्र प्रदेश है, जहां पन्ना जिले में हीरा तो शहडोल में आयरन डिपॉजिट्स है। बीते दिनों सिंगरौली जिले में सोने की खदानें भी मिली हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी निवेशकों को मध्यप्रदेश की रत्नगर्भा भूमि में निवेश करने के लिए आत्मीयता से आमंत्रित करते हुए कहा कि यहां व्यापार की असीम संभावनाएं हैं। आइये और मध्यप्रदेश में अपना दूसरा घर बनाइये। उन्होंने कहा कि निवेशक मध्यप्रदेश में जितने चाहें, उतने उद्योग-धंधे लगाएं, सरकार पलक-पावड़े बिछाकर आपका स्वागत करेगी, आपकी हर संभव मदद करेगी। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में उद्योग-धंधे लगाने के लिए जरूरत के मुताबिक भूमि, बिजली, पानी, कुशल कार्यशक्ति सब उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश और पंजाब दोनों भाइयों की तरह हैं। अनाज के उत्पादन में पंजाब बड़ा और मध्यप्रदेश छोटा भाई है। अब दोनों भाई मिलकर देश और मध्यप्रदेश का विकास करेंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की लुधियाना में प्रमुख उद्योगपतियों से वन-टू-वन चर्चा

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने लुधियाना प्रवास के दौरान पंजाब के प्रमुख उद्योगपतियों से वन-टू-वन बैठक कर उन्हें मध्यप्रदेश की निवेश

निवेश के नए अवसर

अब लुधियाना से मध्यप्रदेश तक

लुधियाना इंटरैक्टिव सेशन से मिले ₹15,606 करोड़ के निवेश प्रस्ताव

सृजित होंगे 20 हजार से अधिक रोजगार के अवसर



क्र.	उद्योग की नाम	वर्ग, पदस्थ	प्रस्तावित निवेश (रु. करोड़ में)	संकेत निवेश (रु. करोड़ में)	अनुमानित रोजगार (संख्या में)
1.	इंटरैक्टिव सेशन	श्री लालचंद गुप्त, चेयरमैन	5000	6000	
2.	लुधियाना इंटरैक्टिव	श्री लालचंद गुप्त, चेयरमैन	2200	2000	
3.	लुधियाना इंटरैक्टिव	श्री एन.पी. ओझा, चेयरमैन	1581	2500	
4.	लुधियाना इंटरैक्टिव	श्री दीपक गर्ग, चेयरमैन	1300	1500	
5.	लुधियाना इंटरैक्टिव	श्री दिनेश ओझा, चेयरमैन	1100	1000	
6.	लुधियाना इंटरैक्टिव	श्री लालचंद गुप्त, चेयरमैन	1000	1800	
7.	लुधियाना इंटरैक्टिव	श्री लालचंद गुप्त, चेयरमैन	700	500	
8.	लुधियाना इंटरैक्टिव	श्री लालचंद गुप्त, चेयरमैन	600	1000	
9.	लुधियाना इंटरैक्टिव	श्री लालचंद गुप्त, चेयरमैन	600	1000	
10.	लुधियाना इंटरैक्टिव	श्री लालचंद गुप्त, चेयरमैन	500	300	
11.	लुधियाना इंटरैक्टिव	श्री लालचंद गुप्त, चेयरमैन	200	750	
12.	लुधियाना इंटरैक्टिव	श्री लालचंद गुप्त, चेयरमैन	100	125	
13.	लुधियाना इंटरैक्टिव	श्री लालचंद गुप्त, चेयरमैन	200	300	
14.	लुधियाना इंटरैक्टिव	श्री लालचंद गुप्त, चेयरमैन	400	1000	
15.	लुधियाना इंटरैक्टिव	श्री लालचंद गुप्त, चेयरमैन	125	500	
	कुल		15,606	20,375	

समर्थक नीतियों से अवगत कराया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उद्योगपतियों को भरोसा दिलाया कि मध्यप्रदेश सरकार जहाँ भी संभावनाएं दिख रही हैं, वहाँ नीतिगत बदलाव करने के लिए पूरी तत्परता से काम करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में श्रमिकों और उद्योगों दोनों के हितों का समान ध्यान रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव से चर्चा करने वाले उद्योगपतियों में टेक्सटाइल सेक्टर से नाहर गुप के सीएमडी श्री दिनेश ओझा, एसईएल गुप के सीएफओ श्री नवनीत गुप्ता और बॉन गुप ऑफ इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधि श्री मंजीत सिंह शामिल रहे। स्टील क्षेत्र से टीके स्टील समूह के एमडी श्री लोकेश जैन ने प्रदेश में संभावित निवेश अवसरों पर चर्चा की। फार्मास्यूटिकल्स, एथेनॉल एवं रसायन क्षेत्र से आईओएल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स के एमडी श्री वरिन्दर गुप्ता और एमआरएम मेथ्या ग्रीनटेक के डायरेक्टर श्री पुनीत अग्रवाल ने निवेश प्रस्ताव रखे। खाद्य प्रसंस्करण और चाय उद्योग से जुड़े भगवती लैक्टो वेजिटेरियन एक्सपोर्ट्स के एमडी श्री सुशील मिश्र और केजी एक्सपोर्ट टीम के सदस्य श्री हरीश दुआ ने मध्यप्रदेश के लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, कृषि उत्पाद उपलब्धता और फूड पार्क्स पर चर्चा की। इंजीनियरिंग सेक्टर से हीरो साइकिल के एमडी श्री एस.के. राय और हाईलैंड एथेनॉल के एमडी श्री अमित कुमार मोदी ने निवेश के लिए औद्योगिक क्षेत्रों की जानकारी ली। इसके अतिरिक्त, बेक्टर्स फूड्स के एमडी श्री अनूप

बेक्टर और ए.वी. कोटस्पिन इंडस्ट्री के डायरेक्टर श्री दीपक गर्ग ने मुख्यमंत्री से विस्तार से चर्चा कर प्रदेश की नीतियों की सराहना की। लुधियाना में हुआ यह संवाद न केवल निवेश प्रस्तावों की दिशा में एक ठोस कदम है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश निवेशकों का भरोसेमंद और व्यवहारिक गंतव्य बनकर उभर रहा है।

पंजाब वीरों की धरती है, इसकी अलग ही पहचान

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश प्रगति पथ पर है। पंजाब वीरों की धरती है, इसकी अलग ही पहचान है। यह गुरु परंपरा की अद्भुत धरती है। मध्यप्रदेश के इंदौर की पहचान स्वच्छता में है, तो लुधियाना की पहचान उद्योगों से है। हम उद्योगपतियों को मध्यप्रदेश में उद्योग लगाने के लिए आमंत्रित करने आए हैं। आप खुले दिल से और बिना किसी हिचक के निवेश करें, सरकार जितनी हो सकेगी, आपकी उतनी मदद करेगी।

स्रोत: मध्यप्रदेश समाचार

Rare Earth Expansion Plan by India Captures Vedanta, JSW Attention

Bhopal: India's ambitious plan to enhance domestic production of rare-earth magnets has sparked significant interest from major conglomerates, including Vedanta Group and JSW Group. The government is crafting an incentive scheme worth up to ₹25 billion (\$290 million) to bolster local manufacturing, aiming to reduce reliance on China, which dominates 90% of global rare-earth processing. This strategic move aligns with India's push to secure critical minerals for electric vehicles (EVs), wind turbines, and defense sectors.

The initiative, still under internal consultation and awaiting cabinet approval, has drawn attention from industry giants. Vedanta, led by billionaire Anil Agarwal, and JSW Group, headed by Sajjan Jindal, alongside EV component maker Sona BLW Precision Forgings, are exploring opportunities in this sector. The policy seeks to encourage private investment by offering subsidies, though the final framework remains fluid. Heavy Industries Minister H.D. Kumaraswamy

recently hinted at these incentives, signaling a broader effort to build a self-reliant supply chain. India holds the world's fifth-largest rare-earth reserves, estimated at 6.9 million tonnes, yet its production capacity lags, contributing only 1% globally compared to China's 69%. The country's dependence on imported magnets, essential for EV traction motors and renewable energy technologies, has become a vulnerability, especially after China imposed export restrictions. Sona BLW's CEO Vivek Vikram Singh emphasized that local magnet production could secure their supply chain, potentially through technology partnerships.

Challenges persist, as rare-earth processing requires advanced technology and years of infrastructure development—areas where China holds a clear edge. State-owned Indian Rare Earths Ltd. currently supplies oxides, but scaling to magnet production demands significant investment and expertise. Industry voices suggest that without substantial subsidies, returns on such



projects could remain negative.

This plan reflects a global trend to diversify rare-earth sources, with India positioning itself as a potential player. Vedanta's exploration of neodymium extraction and JSW's interest in EV manufacturing underscore the economic and strategic stakes. While the initiative's modest budget and ambitious timeline raise questions, it signals India's intent to challenge China's monopoly. Success could transform India into a key supplier in the clean-tech and defense markets, though it hinges on overcoming technical and regulatory hurdles in the coming years.

Source: Business Standard

Invest keeping inflation in mind

Prices of things could double in the next 25 years*

Here is what you have to do

And with this, you can build a corpus that's **more than double** of a regular SIP.

① Don't delay. Start investing early

② Step up your SIP by at least 10% per year

③ Stay invested for a longer period of time

Connect with me to know more

*Considering inflation @6%
Mutual funds are subject to market risks, read the documents carefully before investing.

Vision Invest Tech Private Limited | (+91)7389912025

ARN-10613 | visionadvisorymkt@gmail.com

POWERED BY

wealthy

INVESTMENT AVENUES®

Looking To Invest In Real Properties & Valued Businesses In Bhopal

Discover genuine real estate and well-assessed business opportunities — safe-to-invest and growth-oriented.

Secure Deals. Smart Investments.



EMAIL: INVESTMENTAVENUES90@GMAIL.COM
CONTACT: +91 73899 26586



Sh. Pradeep Karambelkar
Founder & Editor



Dr. Irshad Ahmad Khan
Sub-Editor



Sh. Pushpendra Singh
Marketing Officer

Why Financial Education is now Essential in the Indian Education System?

Financial education is critical in India's education system as the country navigates rapid economic growth and rising digital transactions. With financial frauds costing ₹1.2 lakh crore from 2019 to 2024, equipping students with financial literacy is essential for informed decision-making and security. This article explores why financial education must be integrated into Indian schools, supported by real-world cases and actionable solutions.

The Need for Financial Literacy

India's digital economy is soaring, with 134 billion transactions in 2023 (RBI data). Yet, this growth has spurred financial scams, exploiting those unprepared for complex financial systems. The Indian education system, heavily academic, often overlooks practical skills like budgeting and fraud prevention, leaving young adults vulnerable. Financial education is vital to bridge this gap.

Real-World Impacts of Financial Illiteracy

Case 1: Paytm Investment Scam

In 2023, a Mumbai student lost ₹1.5 lakh to a Paytm-linked investment scam promising high returns. Lured by a fake app, he shared banking details, unaware of red flags. Basic financial literacy could have helped him verify the offer's legitimacy.

Case 2: Phishing Attacks

The Indian Cybercrime Coordination Centre noted a 45% surge in phishing attacks in 2024. A Delhi student lost ₹2.3 lakh after sharing OTPs via a fake bank link. Education on digital security, like spotting phishing attempts, could have prevented this.

Case 3: Insurance Mis-selling

A Chennai teacher lost ₹3 lakh in 2023 to a mis-sold insurance policy marketed as a "guaranteed return" plan. Unfamiliar with

policy terms, she made an uninformed choice. Financial education could teach students to scrutinize such products.

Why Financial Education Matters

1. Informed Decision-Making

Financial literacy empowers students to manage money wisely. Lessons on budgeting, interest rates, and loans promote smart choices. For example, understanding compound interest encourages early savings, while loan literacy prevents debt traps.

2. Fraud Prevention

With fraudsters leveraging technology, education on spotting scams—like unsolicited offers or suspicious links—reduces risks. Knowledge of two-factor authentication could have saved the Delhi student from phishing losses.

3. Long-Term Financial Stability

India's youth face a complex financial world with easy access to credit and investment apps. Without guidance, poor decisions can lead to ruin. Lessons on diversification and emergency funds foster lasting security.

4. Reducing Inequality

Financial illiteracy disproportionately affects marginalized groups. School-based financial education promotes economic inclusion, empowering diverse students to navigate financial systems confidently.

Challenges in Implementing Financial Education

While the need is clear, integrating financial education into India's education system faces challenges:

- **Curriculum Overload:** Schools already juggle a packed curriculum, making it difficult to add new subjects.

- **Teacher Training:** Educators may lack the expertise to teach financial concepts effectively.

- **Regional Disparities:** Rural schools may have fewer resources to implement financial education programs.

Solutions include embedding financial modules in subjects like economics, partnering with organizations like the National Financial Literacy and Inclusion Council for training, and leveraging digital tools for scalable resources.

Global Examples to Emulate

Countries like Australia and Singapore have successfully embedded financial education in their curricula. Australia's "MoneySmart" program, for instance, teaches students about budgeting, taxes, and investments through interactive modules. India can adopt similar age-appropriate programs, tailored to its cultural and economic context, to prepare students for financial independence.

Conclusion

The rising incidence of financial frauds and losses in India highlights the urgent need for financial education in schools. By equipping students with the knowledge to navigate the financial world, the education system can empower them to avoid scams, make informed decisions, and build secure futures. Cases like the Paytm scam, phishing attacks, and insurance mis-selling serve as stark reminders of the cost of financial illiteracy. Integrating financial education into the Indian education system is not just a reform—it is a necessity for a financially resilient future.

Dr. Irshad Ahmod
Khan
Sub-Editor



आईटीसी बढ़ाएगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भागीदारी, कृषि उत्पाद होंगे हाई वैल्यू

भोपाल: आईटीसी लिमिटेड ने अपनी कृषि व्यवसाय रणनीति को और मजबूत करने की घोषणा की है। कंपनी की 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, आईटीसी का ध्यान मूल्यवर्धित कृषि उत्पादों (वैल्यू-एडेड एग्री प्रोडक्ट्स) के पोर्टफोलियो को तेजी से बढ़ाने पर केंद्रित है। यह व्यवसाय 22 राज्यों में फैला हुआ है और प्रति वर्ष 35 लाख टन से अधिक की मात्रा को संभालता है, जिसमें मसाले, कॉफी, फ्रोजन समुद्री उत्पाद और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ शामिल हैं।

रिपोर्ट में बताया गया कि आईटीसी के कृषि व्यवसाय ने 2024-25 में 25 प्रतिशत की राजस्व वृद्धि दर्ज की, जो 19,753 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। कंपनी ने मसालों जैसे कि मिर्च, जीरा, हल्दी और धनिया के क्षेत्र में अपनी स्थिति को और मजबूत किया है, जिससे यह खरीदारों के लिए पसंदीदा आपूर्ति श्रृंखला साझेदार बन गई है। इसके अलावा,

आईटीसी ने जैविक और एकीकृत फसल प्रबंधन कार्यक्रमों को बढ़ावा देकर कई राज्यों में जैविक खेती का विस्तार किया है, ताकि बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके।

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी आईटीसी ने अपनी उपस्थिति को मजबूत किया है, विशेष रूप से यूरोप और मध्य पूर्व में। कंपनी मूल्यवर्धित फ्रोजन समुद्री उत्पादों के निर्यात में अग्रणी है। 2024-25 में, वैश्विक कॉफी कीमतों में वृद्धि के बावजूद, भारत के प्रमुख कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में रणनीतिक सोर्सिंग के माध्यम से निर्यात में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई। आईटीसी की 'आईटीसी मार्स' (मेटामार्केट फॉर एडवांस्ड एग्रीकल्चर/एग्रीकल्चर एंड रूरल सर्विसेज) पहल ने भी किसानों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह 'फिजिटल' (भौतिक और डिजिटल) मंच 11 राज्यों में 21 लाख से अधिक

डिजिटल) मंच 11 राज्यों में 21 लाख से अधिक किसानों को जोड़ता है, जो उन्हें एआई-आधारित कृषि सलाह और बाजार पहुंच प्रदान करता है।

कंपनी ने कहा कि उसका लक्ष्य टिकाऊ और समावेशी विकास के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। पिछले दस वर्षों में, आईटीसी समूह ने लगभग 9.5 बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा अर्जित की, जिसमें कृषि निर्यात का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा है। यह उपलब्धि छोटे किसानों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने में कंपनी के योगदान को दर्शाती है।

आईटीसी की यह रणनीति न केवल कंपनी की वृद्धि को गति देगी, बल्कि भारतीय कृषि क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाएगी।

IRB InvIT Unitholders Greenlight Full Acquisition of 3 SPVs from IRB Infrastructure Trust

Bhopal: The unitholders of IRB InvIT Fund have unanimously approved the acquisition of a 100% stake in three special purpose vehicles (SPVs) from IRB Infrastructure Trust, marking a significant expansion in the company's infrastructure portfolio. The deal, valued at ₹8,436 crore as of 30 June 2025, was endorsed by a 96% majority, as announced in an exchange filing on 4 July 2025.

The SPVs—IRB Hapur Moradabad Tollway, Kaithal Tollway, and Kishangarh Gulabpura Tollway—comprise three build-operate-transfer (BOT) highway assets. This acquisition, facilitated by IRB Infrastructure Trust, a private InvIT associate of IRB Infrastructure Developers, will bolster IRB InvIT Fund's asset base. The transaction is part of a strategic move to enhance the public InvIT's portfolio, which is sponsored by IRB Infrastructure Developers, India's largest integrated private toll road and highway developer.

Virendra D Mhaikar, Chairman and Managing Director of IRB Infrastructure

Developers, expressed gratitude to the unitholders, stating, "This approval reflects their strong trust in our growth strategy. We remain committed to enhancing unitholder value by adding quality assets." The acquisition is expected to increase the company's operations and maintenance (O&M) order book by approximately ₹3,100 crore, elevating the total order book to ₹33,600 crore.

The deal, initially outlined in a binding term sheet signed on 30 May 2025, is subject to regulatory approvals. Post-acquisition, IRB InvIT Fund plans to raise up to ₹5,000 crore to support the expansion, with unitholders also approving the sponsor's appointment as project manager for the SPVs' O&M activities. This move strengthens IRB's position across 12 states, with an asset base exceeding ₹80,000 crore.

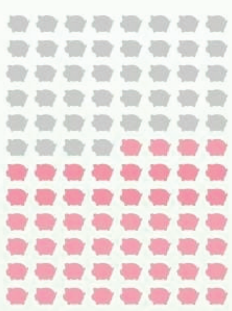
The acquisition underscores IRB's focus on consolidating its highway infrastructure dominance. The three SPVs, spanning critical highway stretches, are



anticipated to generate stable revenue streams, aligning with the company's goal of delivering sustainable returns. This development is seen as a step toward unlocking capital for future infrastructure projects, including potential toll-operate-transfer (TOT) opportunities. As India's infrastructure sector continues to grow, this acquisition positions IRB InvIT Fund to play a pivotal role in the nation's highway network expansion, promising long-term value for investors and supporting the country's economic development.

Source: Economics Times

People rely on credit and savings Not on Insurance



of families paid their last hospital bills from their **own pocket**.



had to take **loans** or fall into **debt**.



used **insurance**

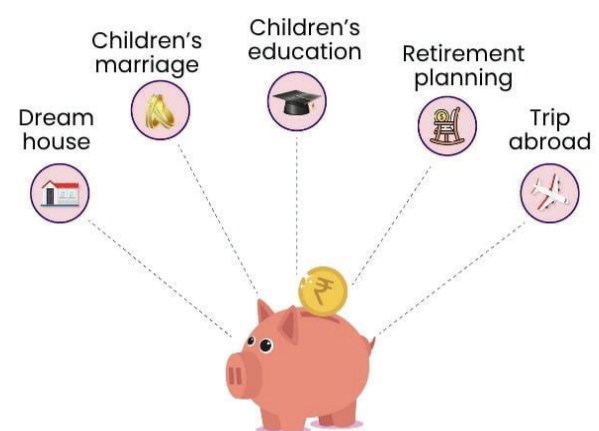
Which one do you fall in?

Buy health insurance to safeguard your savings and avoid a debt trap.



Source: bt Money today

Fulfill all financial goals Through SIP



An investment of **₹15,000/month** can become over **₹2.5 crore** in **25 years**

Want to invest through SIP?

Connect with me to know more

*Assumed returns @12%
Mutual funds are subject to market risks, read the documents carefully before investing.

India Reshapes Energy Policy, Ends Longstanding Renewable Subsidy

Bhopal: India has officially ended a key subsidy that played a pivotal role in driving the growth of its renewable energy sector, despite intense lobbying from the industry. The decision, effective from 1 July, requires solar and wind power projects commissioned after June to bear 25% of the transmission costs across states, with charges set to rise for future plants as per a federal power regulator plan.

This policy shift marks the end of a financial incentive that significantly boosted the clean energy boom, enabling India to expand its renewable capacity. However, it now introduces financial strain on a sector already facing a demand glut and high-power prices. Industry experts warn that this could increase green energy tariffs by approximately 0.4 rupees per kilowatt-hour—a 16% rise compared to

the lowest auction prices in fiscal year 2025. This change threatens to complicate the signing of power purchase agreements, particularly for projects already auctioned.

The National Solar Energy Federation of India's CEO, Subrahmanyam Pulipaka, highlighted the concern, stating that the cost increase could hinder progress. With nearly 30 gigawatts of upcoming capacity struggling to secure long-term distribution, India's ambitious target of achieving 500 gigawatts of clean energy installations by 2030 is now under pressure.

A notable consequence could be the decentralization of renewable energy production. Previously,

cheaper transmission encouraged the concentration of projects in five states with optimal solar radiation, strong winds,

and abundant land. Now, states may prioritize local projects to avoid inter-state transmission charges, as seen with Karnataka's plan to develop energy closer to home.

While the move aims to streamline costs, it raises questions about the government's commitment to its clean energy goals. The renewable sector, which has seen rapid growth, now faces a critical juncture as it navigates this new financial landscape.

Source: Business Standard



TATA AutoComp and Škoda Group Launch JV to Produce Railway Components in India

Bhopal: TATA AutoComp Systems and Škoda Group announced a joint venture to manufacture railway propulsion systems and components in India, backed by a multi-million-euro investment. This strategic partnership aims to tap into India's rapidly growing railway and urban mobility markets, aligning with the "Make in India" initiative to foster local production and technological advancement.

The joint venture will focus on producing advanced components, including converters, drives, and auxiliary converters, for medium to high-speed trains, regional trains, metros, and light rail vehicles. Manufacturing operations will be based in India, leveraging TATA

AutoComp's extensive experience in the Indian railway sector, notably its contributions to the Vande Bharat train project, and Škoda Group's European expertise in reliable, energy-efficient rail systems. Arvind Goel, Vice-Chairman of TATA AutoComp, emphasized that the collaboration will strengthen the company's footprint in the railway and metro sectors by introducing cutting-edge electrical propulsion systems. Petr Novotný, CEO of Škoda Group, highlighted the partnership's role in bringing proven European technology to India, supporting sustainable mobility solutions.

The venture is expected to drive economic growth and job creation while enhancing

India's rail infrastructure with environmentally friendly and efficient systems. The signing ceremony, held at the Hotel Taj Mahal in New Delhi, was attended by senior leadership and Ing. Eva Kopecká from the Embassy of the Czech Republic.

This collaboration marks a significant step for TATA AutoComp in diversifying its portfolio beyond electric vehicle components and reinforces Škoda Group's global expansion strategy, positioning both companies to meet the rising demand for modern rail solutions in India.

Source: Economics Times

चुनौतीपूर्ण FY25 के बाद अपोलो टायर्स आशावादी दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहा है

भोपाल: वित्तीय वर्ष 2025 (FY25) में कई चुनौतियों का सामना करने के बाद, अपोलो टायर्स भविष्य के अवसरों के प्रति सावधानीपूर्वक आशावाद के साथ आगे बढ़ रहा है। कंपनी के चेयरमैन ओंकार कंवर ने वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि FY25 में भारत और यूरोप में प्रदर्शन अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहा, फिर भी कंपनी ने अपनी रणनीति को मजबूत करने और टिकाऊ विकास पर ध्यान केंद्रित किया।

कंपनी का परिचालन राजस्व FY25 में 3% बढ़कर 26,123 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल 25,378 करोड़ रुपये था। हालांकि, शुद्ध लाभ 1,121 करोड़ रुपये पर आ गया, जो पिछले वित्तीय वर्ष के 1,722 करोड़ रुपये से कम है। इस गिरावट के बावजूद, कंवर ने कहा कि कंपनी ने टिकाऊ और लाभकारी विकास को प्राथमिकता दी, न कि हर हाल में वृद्धि को।

आने वाले समय के लिए, अपोलो टायर्स अपने हंगरी और आंध्र प्रदेश संयंत्रों में यात्री कार रेडियल (PCR) क्षमता विस्तार के लिए 1,500 करोड़ रुपये के निवेश की योजना बना रही है।

यह कदम कंपनी की भविष्य के लिए तैयार करने की रणनीति का हिस्सा है। उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नीरज कंवर ने कहा कि कंपनी बाजार के विकास और परिचालन दक्षता पर नजर रखते हुए टिकाऊ विकास पर ध्यान दे रही है।

कंपनी का मानना है कि डिजिटलाइजेशन, सस्टेनेबिलिटी और नवाचार भविष्य की कुंजी हैं। चुनौतियों के बावजूद, अपोलो टायर्स अस्थिरता से निपटने और दीर्घकालिक अवसरों का लाभ उठाने के लिए अपने लोगों, प्रक्रियाओं और क्षमताओं में निवेश कर रही है। यह दृष्टिकोण भारत के टायर उद्योग में उसकी स्थिति को मजबूत कर सकता है, जहां कच्चे माल की कीमतों और मांग में उतार-चढ़ाव निरंतर चुनौती बने हुए हैं।

Source: ET



No Impact of 50% US Copper Tariffs on Indian Firms, Industry Says

Bhopal: The recent announcement by US President Donald Trump imposing a 50% tariff on copper imports is unlikely to affect Indian companies, according to industry experts. India's copper sector remains insulated due to the country's status as a copper-deficient nation with negligible exports to the US, a fact underscored by the strong domestic demand driven by renewable energy and electric vehicle (EV) sectors.

International Copper Association India Managing Director Mayur Karmarkar emphasized that India's copper exports are minimal, with shipments to the US amounting to just around 10,000 tonnes annually. "India is a copper-deficient country, and its exports are not significant. The proposed duty will not impact Indian firms, especially given the buoyant domestic demand fueled by India's focus on renewable energy, EVs, and other copper-intensive industries," Karmarkar stated. This resilience is further supported by India's role as a net importer, with 1 million tonnes of copper concentrate imported in 2023, primarily from Indonesia (27%), Chile (25%), Peru (14%), and Panama (9%).

Coal and Mines Minister G Kishan Reddy confirmed that India will engage in discussions to assess any broader implications of the US tariffs. However, the immediate outlook suggests limited concern. The US tariff, announced on July 8, 2025, follows similar duties on steel and aluminium, aiming to bolster domestic production. Yet, India's import-dependent market structure shields it from direct fallout, as the country relies on foreign supplies to meet its growing needs.

A vision document released by Reddy forecasts a sixfold increase in copper demand by 2047, with plans to boost smelting and refining capacity by 5 million tonnes annually by 2030. This strategic push aligns with India's goal to enhance its copper value chain, reducing reliance on imports over time. The tariff's impact on global copper prices, which spiked over 10% before easing, has not disrupted India's market dynamics significantly. Industry leaders view this as an opportunity to strengthen domestic infrastructure and explore alternative export markets. While the US decision may reshape global trade flows, India's focus on self-sufficiency and renewable energy

growth ensures its copper sector remains unaffected. The ongoing dialogue with the US will further clarify any long-term trade adjustments, but for now, Indian companies stand firm against the tariff's ripple effects.

Source: Business Standard



ईजमाइट्रिप के सह-संस्थापक ने एआई वेंचर स्टूडियो की शुरुआत की, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए

भोपाल: ट्रेवल बुकिंग प्लेटफॉर्म ईजमाइट्रिप के सह-संस्थापक रिकांत पिट्टी ने भारत के उद्यमी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए एक नया कदम उठाया है। उन्होंने एक एआई वेंचर स्टूडियो की शुरुआत की घोषणा की है, जो स्वास्थ्य, रक्षा, मोबिलिटी, मनोरंजन, लॉजिस्टिक्स, एग्रीटेक, फिनटेक और शिक्षा जैसे विविध क्षेत्रों में स्टार्टअप्स को पोषण और समर्थन प्रदान करेगा। यह पहल पारंपरिक निवेश मॉडल से हटकर एक सहयोगात्मक भागीदारी पर केंद्रित है, जिसमें पिट्टी स्वयं इन नवाचारों को विकसित करने में हाथ बंटाएंगे।

पिट्टी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इस पहल की घोषणा करते हुए कहा, "पिछले कुछ महीनों में कई जुझारू उद्यमियों ने मेरे पास नवीन और शक्तिशाली विचारों के साथ संपर्क किया, लेकिन उन्हें उचित समर्थन नहीं मिल पा रहा था। इससे मुझे विचार आया कि मैं केवल निवेश ही नहीं, बल्कि उनके साथ मिलकर निर्माण करूं।" यह वेंचर स्टूडियो स्टार्टअप्स की पहचान और पोषण पर ध्यान केंद्रित करेगा, जो भारत को वैश्विक तकनीकी केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

ईजमाइट्रिप, जो 2008 में स्थापित हुआ और 2021 में सार्वजनिक हुआ, भारत का दूसरा सबसे बड़ा ऑनलाइन ट्रेवल प्लेटफॉर्म बन चुका है। पिट्टी का अनुभव इस बात का प्रमाण है कि भारतीय स्टार्टअप्स को बड़े पैमाने पर सफलता मिल सकती है। उनकी यह नई पहल भारत के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद अवसरों और चुनौतियों के बीच आती है, जहां एक ओर भारी निवेश और यूनिकॉर्न कंपनियों का उदय हुआ है, वहीं प्रारंभिक चरण के उद्यमियों को मार्गदर्शन और समर्थन की कमी का सामना करना पड़ता है।

एआई-चालित समाधानों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ, यह स्टूडियो वैश्विक तकनीकी रुझानों के अनुरूप है, जहां AI विभिन्न उद्योगों में क्रांति ला रही है। भारत का विशाल तकनीकी और इंजीनियरिंग प्रतिभा पूल, साथ ही विविध बाजार चुनौतियां, इसे वैश्विक एआई परिदृश्य में एक मजबूत खिलाड़ी बना सकती हैं। पिट्टी ने कहा कि यह पहल अगले कुछ महीनों में संचालन शुरू करेगी और देश भर से उद्यमियों से आवेदन आमंत्रित करेगी।

यह कदम न केवल भारतीय उद्यमिता को प्रोत्साहन देगा, बल्कि रोजगार सृजन और नवाचार को भी बढ़ावा देगा। आने वाले समय में यह स्टूडियो भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

Source: Economics Times

ज़ेप्टो 450-500 मिलियन डॉलर जुटाने की तैयारी में, 7 अरब डॉलर के मूल्यांकन के साथ: रिपोर्ट

भोपाल: भारत की तेजी से बढ़ती ग्रॉसरी और फूड डिलीवरी स्टार्टअप ज़ेप्टो जल्द ही 450-500 मिलियन डॉलर की नई फंडिंग जुटाने की योजना बना रही है, जिसके साथ उसका मूल्यांकन 7 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। सीएनबीसी टीवी-18 की रिपोर्ट के अनुसार, यह फंडिंग पिछले साल के 5 अरब डॉलर के मूल्यांकन से 40% की वृद्धि को दर्शाती है। यह कदम कंपनी को भारत के तेजी से बढ़ते क्लिक कॉमर्स क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद करेगा।

रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा निवेशक जनरल कैटलिस्ट और एवेनियर ग्रोथ इस दौर का नेतृत्व करेंगे, जबकि अन्य निवेशक भी इसमें हिस्सा लेंगे। फंडिंग की प्रक्रिया उन्नत चरण में है और जल्द ही पूरी होने की उम्मीद है। ज़ेप्टो ने पिछले साल 1.35 अरब डॉलर जुटाए थे, और इस नई पूंजी से कंपनी अपनी विस्तार योजनाओं को गति देगी। कंपनी का मुख्यालय हाल ही में सिंगापुर से भारत स्थानांतरित किया गया है, जो उसके आईपीओ की तैयारी का हिस्सा है।

ज़ेप्टो, जो स्विगी इंस्टामार्ट और ज़ोमैटो की ब्लिंकिट जैसी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करती है, अपने 10 मिनट की डिलीवरी सेवा के लिए जानी जाती है। इस फंडिंग से कंपनी अपने डार्क स्टोर नेटवर्क का विस्तार और तकनीकी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की योजना बना रही है। सीईओ आदित पालिचा का कहना है कि यह कदम ग्राहक अनुभव को बेहतर करने और लाभप्रदता बढ़ाने के लिए उठाया गया है।

यह कदम भारत के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में निवेशकों के भरोसे को दर्शाता है। हालांकि, बढ़ती प्रतिस्पर्धा और बाजार की चुनौतियों के बीच कंपनी को अपनी रणनीति को प्रभावी बनाए रखना होगा।



जियो ब्लैकरॉक का शानदार आगाज: डेब्यू NFO से ₹17,800 करोड़ की राशि जुटाई

भोपाल: जियो ब्लैकरॉक एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने अपने पहले न्यू फंड ऑफर (NFO) के जरिए बाजार में धमाकेदार एंट्री की है। कंपनी ने तीन दिन की अवधि में कुल ₹17,800 करोड़ की राशि जुटाई, जो भारतीय म्यूचुअल फंड उद्योग में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस सफलता में 90 से अधिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और 67,000 से ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स ने हिस्सा लिया।

अभूतपूर्व प्रतिक्रिया

यह NFO, जो 30 जून से 2 जुलाई 2025 तक खुला रहा, ने जियो ब्लैकरॉक ओवरनाइट फंड, जियो ब्लैकरॉक लिक्विड फंड, और जियो ब्लैकरॉक मनी मार्केट फंड जैसे तीन डेट स्कीम्स के माध्यम से यह राशि जुटाई। कंपनी के एक बयान के अनुसार, इसने न केवल बड़े निवेशकों का भरोसा जीता, बल्कि खुदरा निवेशकों की भारी भागीदारी ने भी इसे विशेष बनाया। यह राशि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैकरॉक

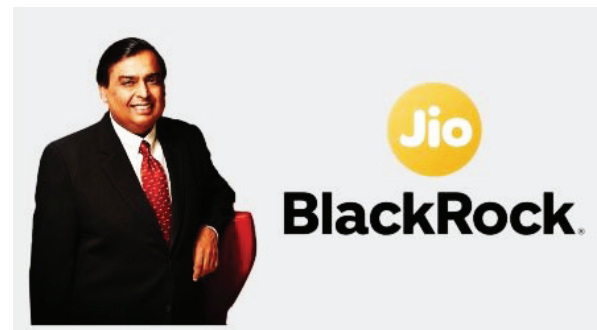
की 50:50 संयुक्त पहल की मजबूत शुरुआत को दर्शाती है।

बाजार में नया मुकाम

इस उपलब्धि के साथ जियो ब्लैकरॉक अब भारत के शीर्ष 15 एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (डेट एयूएम के आधार पर) में शामिल हो गया है, जो कुल 47 फंड हाउसेज में से एक है। कंपनी का डिजिटल-प्रथम और डेटा-चालित निवेश दृष्टिकोण निवेशकों के बीच भरोसा और उत्साह पैदा कर रहा है। जियो ब्लैकरॉक के प्रबंध निदेशक और सीईओ सिद्ध स्वामीनाथन ने कहा कि यह प्रतिक्रिया कंपनी के नवाचार और जोखिम प्रबंधन क्षमताओं का प्रमाण है।

निवेशकों के लिए अवसर

ये फंड छोटी अवधि के निवेश के लिए उपयुक्त माने जा रहे हैं, जो तरलता और जोखिम-प्रबंधन के बीच संतुलन प्रदान करते हैं।



विशेषज्ञों का मानना है कि जियो ब्लैकरॉक की यह पहल म्यूचुअल फंड क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएगी और लाखों भारतीयों के लिए निवेश को सस्ता एवं सुलभ बनाएगी।

स्रोत: Bhaskar News

Adani Enterprises Plans Rs 1,000 Crore Fundraise Through NCDs

Bhopal: Adani Enterprises, the flagship company of the Adani Group, has announced plans to raise Rs 1,000 crore through the issuance of Non-Convertible Debentures (NCDs). The move is aimed at strengthening the company's financial position and supporting its ongoing expansion across diverse sectors.

The company disclosed in a regulatory filing that the NCDs will be issued on a private placement basis, targeting institutional investors and high-net-worth individuals. The funds are expected to be utilized for capital expenditure, debt repayment, and other corporate purposes, aligning with Adani Enterprises' growth strategy in infrastructure, energy, and utilities.

This fundraise comes as part of the conglomerate's broader efforts to diversify its funding sources amid a dynamic economic environment. The NCDs, which offer fixed returns and are

not convertible into equity, are likely to attract investors seeking stable investment opportunities. Market analysts suggest that the issuance reflects Adani Enterprises' confidence in its long-term growth prospects, despite global economic uncertainties.

The terms of the NCDs, including tenure, interest rates, and other specifics, will be finalized closer to the issuance date, subject to regulatory approvals. The company has not yet disclosed the exact timeline for the issuance but emphasized its commitment to maintaining transparency and compliance with all regulatory requirements.

Adani Enterprises has been actively expanding its portfolio, with significant investments in renewable energy, airports, and data centers. The Rs 1,000 crore fundraise is expected to bolster these initiatives, positioning the company to capitalize on emerging opportunities in



India's rapidly growing infrastructure and energy sectors.

The announcement has generated interest among investors, with market watchers closely monitoring the conglomerate's financial strategies. Adani Enterprises' stock performance and investor sentiment will likely be influenced by the successful execution of this fundraising plan.

Source: Mint

अदाणी पावर ने 600 मेगावाट विदर्भ पावर का अधिग्रहण पूरा किया

भोपाल: भारत की अग्रणी निजी थर्मल पावर उत्पादक कंपनी अदाणी पावर लिमिटेड (एपीएल) ने विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड (वीआईपीएल) के 600 मेगावाट की क्षमता वाले संयंत्र का अधिग्रहण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस सौदे की कीमत 4,000 करोड़ रुपये है। महाराष्ट्र के नागपुर जिले के बुटीबोरी में स्थित यह 2x300 मेगावाट का कोयला आधारित पावर प्लांट अब अदाणी पावर की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गया है।

यह अधिग्रहण 7 जुलाई 2025 को प्रभावी हुआ, जब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) की मुंबई बेंच ने 18 जून 2025 को अदाणी पावर की रिजॉल्यूशन योजना को मंजूरी दी थी। इस अधिग्रहण के साथ कंपनी की संचालन क्षमता 18,150 मेगावाट तक पहुंच गई है। वीआईपीएल पहले कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के तहत थी, जिसे दिवालियापन और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के तहत संभाला गया।

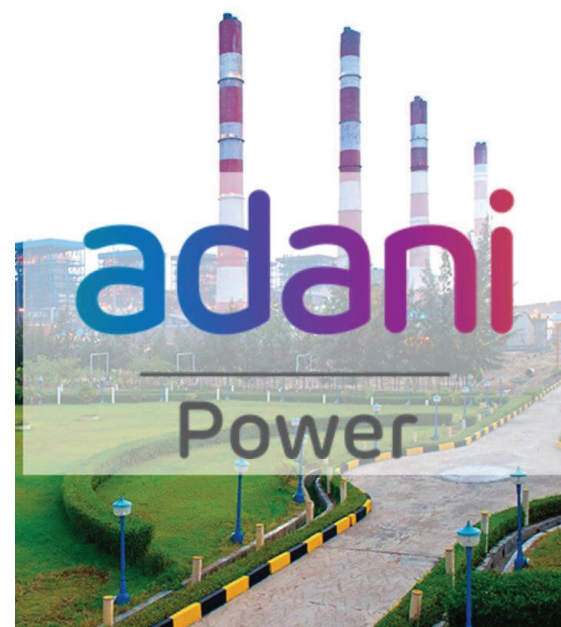
अदाणी पावर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एसबी ख्यालिया ने कहा, "वीआईपीएल का अधिग्रहण तनावग्रस्त संपत्तियों को पुनर्जीवित

और मूल्य सृजन की हमारी रणनीति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। हम अपने पोर्टफोलियो का विस्तार जारी रखते हुए भारत के 'सभी के लिए बिजली' के विजन को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो देश की सतत वृद्धि को गति देगा।"

कंपनी ने अपने बेस लोड पावर उत्पादन पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड परियोजनाओं का मिश्रण अपनाया है। वर्तमान में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 1,600 मेगावाट की छह अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल पावर प्लांट्स का निर्माण चल रहा है। इसके अलावा, कोरबा में 1,320 मेगावाट के सुपरक्रिटिकल प्लांट का पुनरुद्धार भी किया जा रहा है। कंपनी का लक्ष्य वित्त वर्ष 2029-30 तक 30,670 मेगावाट की परिचालन क्षमता हासिल करना है।

यह कदम अदाणी पावर को भारत की सबसे बड़ी निजी बेस लोड पावर उत्पादन कंपनी के रूप में मजबूत करता है, जो देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

Source: Economics Times



WEEKLY STOCK PIVOT LEVEL

All level indicated above are based on future prices PP: Pivot Point: This is TRIGGER POINT for buy/sell Based on the price range of the previous Month, R1: Resistance one: 1st Resistance over PP; R2: resistance Two: 2nd Resistance over R1; S1: Support one: 1st support after PP; S2: Support Two: 2nd support after S1

- As per tool, trader should take Buy position just above pp and keep the stop loss of PP and 1st target would be R1
- If R1 is crossed then R2 becomes the next target with the stop loss at R1

Anil Bhardwaj

Technical Head

anil.stockcare@gmail.com

- If R2 is crossed then R3 becomes the next target with the stop loss at R2.
- Similarly, if price goes below PP the trader should SELL price below PP as stop loss and the first target would be S1,
- If S1 is crossed then S2 becomes the next target with the stop loss at S1,
- If S2 is crossed then S3 becomes the next target with the stop loss at S2.

Stock name	closing	R3	R2	R1	PP	S1	S2	S3
NIFTY	25150	25840	25693	25421	25275	25003	24857	24585
BANK NIFTY	56755	57920	57630	57192	56902	56464	56174	55736
FINNIFTY	26853	27428	27275	27064	26919	26708	26563	26352
MIDCAP	13027	13793	13627	13327	13161	12861	12695	12395
ACC	1978	2108	2068	2023	1983	1938	1898	1853
AXISBANK	1172	1201	1190	1181	1170	1161	1150	1141
ABCAPITAL	269	286	282	275	271	264	260	253
BHARTIARTL	1925	2131	2085	2005	1959	1879	1833	1753
BHEL	258	274	269	263	259	253	249	243
BIOCON	373	396	389	381	374	366	359	351
CDSL	1687	1868	1831	1759	1722	1650	1613	1541
DATAPATTERN	2854	3179	3108	2981	2910	2783	2712	2585
ESCORTS	3302	3491	3444	3373	3326	3255	3208	3137
EICHERMOTOR	5607	5817	5768	5687	5638	5557	5508	5427
FEDERAL BANK	207	224	220	213	210	203	200	193
GRINFRAPROJECT	1263	1327	1346	1304	1273	1231	1200	1158
HDFCBANK	1983	2046	2031	2007	1992	1968	1953	1929
HCLTECH	1633	1790	1758	1695	1663	1600	1568	1505
HINDUNILVR	2520	2775	2652	2586	2463	2397	2274	2208
HAL	4860	5255	5160	5010	4915	4765	4670	4520
HYUNDAI	2107	2268	2212	2159	2103	2050	1994	1941
IOC	150	158	156	153	151	148	146	143
ICICIBANK	1422	1469	1457	1439	1427	1409	1397	1379
INFY	1595	1722	1684	1639	1601	1556	1518	1473
ITC	417	428	424	420	416	412	408	404
KOTAKBNK	2216	2386	2314	2265	2193	2144	2072	2023
LICHOUSING	603	623	617	610	604	597	591	584
LT	3537	3666	3640	3588	3562	3510	3484	3432
LUPIN	1891	2077	2034	1962	1919	1847	1804	1732
MARUTI	12585	13026	12848	12716	12538	12406	12228	12096
M&M	3070	3276	3233	3151	3108	3026	2983	2901
MGL	1478	1633	1594	1536	1497	1439	1400	1342
MAZGAONDOC	3160	3450	3388	3274	3212	3098	3036	2922
PFC	430	470	454	442	426	414	398	386
RECLTD	400	420	412	406	398	392	384	378
RELIANCE	1494	1594	1572	1533	1511	1472	1450	1411
SBIN	809	826	821	815	810	804	799	793
SUNPHARMA	1674	1723	1702	1688	1667	1653	1632	1618
SHRIRAMFINANCE	667	707	697	682	672	657	647	632
TITAN	3361	3924	3810	3585	3471	3246	3132	2907
TCS	3265	3537	3481	3373	3317	3209	3153	3405
TATAMOTORS	679	712	705	692	685	672	665	652
UPL	653	722	705	679	662	636	619	593
VALIENT	407	451	441	424	414	397	387	370
WIPRO	258	278	274	266	262	254	250	242

Tata Motors Faces 9% Sales Decline Globally in Q1 2025

Bhopal: Tata Motors, a leading Indian automaker, reported a 9% drop in global wholesales for the first quarter of fiscal year 2026 (Q1 FY26), ending June 2025. The company sold 2,99,664 units, down from 3,29,847 units in the same period last year, according to an exchange filing. The decline reflects challenges across its passenger and commercial vehicle segments, including its luxury subsidiary Jaguar Land Rover (JLR). Passenger vehicle sales fell 10% to 1,24,809 units, with electric vehicle sales showing a slight recovery toward the quarter's end, reaching 16,231 units. Commercial vehicle sales, including the Tata Daewoo range, dropped 6% to 87,569 units, though international business in this segment grew by 68%. JLR's global wholesales declined 11% to 87,286 units, impacted by the phasing out of legacy Jaguar models and new US tariffs.

The downturn was attributed to softer demand in domestic and international markets, particularly in May and June, amid economic uncertainties and seasonal factors. However, the company highlighted resilience in its electric vehicle segment and international commercial vehicle growth as positive signs. Tata Motors' Managing Director, Shailesh Chandra, noted that new model launches like the refreshed Tiago and Harrier.ev are expected to boost momentum in the coming months.

Despite the decline, the company remains optimistic, citing a healthy monsoon forecast, potential repo rate cuts, and renewed infrastructure focus as drivers for future growth. Tata Motors is also expanding its global footprint, entering markets like Egypt, and enhancing product offerings with innovations such as the Ace Pro mini-truck. This performance underscores the need for strategic adjustments to navigate a competitive and evolving automotive landscape.

Source: Punjab Kesari

Disclaimer: This content is for educational purposes only. Investments are subject to market risks. Please conduct your own research or consult a qualified financial advisor before making any investment decisions. Investments are subject to market risks. Please conduct your own research or consult a qualified financial advisor before making any investment decisions.